



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 8 मार्च, 2004/18 फाल्गुन, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिना शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 19 फरवरी, 2004

संख्या शिमला एल०एफ० मिस कोटखाई-224-22-26.--एतद्वारा श्री सुन्दर सिंह, सदस्य, नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 18 (1) (च) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के पश्चात् किसी ऐसी निरुद्धता के अधीन हो गया है जो यदि उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन के समय विद्यमान रही होती, तो उसको निर्वाचन या नाम निर्देशन के लिए उम्मीदवारों की शर्तों को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अमान्य बना देती या यदि यह प्रतीत होता है कि वह अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के समय ऐसी किसी निरुद्धता का भाजन था।

यह कि सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कोटखाई द्वारा पारित आदेश 8-1-2004 द्वारा श्री सुन्दर सिंह उपरोक्त द्वारा सरकारी भूमि खाता खतोनी नं० 63/120 मिन खसरा नम्बर 295 व 296, किता 2 रकबा 0-02-15 हैक्टेयर स्थित चक चलनैर पटवार वृत बाग, तहसील कोटखाई पर कब्जा नाजायज पाया गया। इसलिये आप हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 18 (1) के प्रावधान अनुसार नगर पंचायत कोटखाई के सदस्य पद पर रहने के लिए निरहित हो गये हैं।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सुन्दर सिंह, सदस्य, नगर पंचायत कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूँ कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें इस कृत्य के लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से निरहित किया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

शिमला, 19 फरवरी, 2004

संख्या शिमला एल०एफ०मिस० कोटखाई 224-27-31.—एतद्वारा श्रीमती कविता चौहान, अध्यक्ष, नगर पंचायत कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 18 (1) (च) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के पश्चात् किसी ऐसी निरर्हता के अधीन हो गया है जो यदि उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन के समय विद्यमान रही होती, तो उसको निर्वाचन या नाम निर्देशन के लिए उम्मीदवारों की अर्हताओं को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपात्र बना देती या यदि यह प्रतीत होता है कि वह अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के समय ऐसी किसी निरर्हता का भाजन था।

यह कि सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कोटखाई द्वारा पारित आदेश 8-1-2004 द्वारा श्री सुन्दर सिंह, सदस्य नगर पंचायत कोटखाई जो कि आपके पति हैं के द्वारा सरकारी भूमि खाता खतोनी नं० 63/120 मिन खसरा नम्बर 295 व 296 किता 2 रकबा 0-02-15 हैक्टेयर स्थित चक चलनैर, पटवार वृत बाग तहसील कोटखाई पर कब्जा नाजायज पाया गया। इसलिये आप हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 18 (1) के प्रावधान अनुसार नगर पंचायत कोटखाई के अध्यक्ष पद पर रहने के लिए निरहित हो गये हैं।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीमती कविता चौहान, अध्यक्ष, नगर पंचायत कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूँ कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें इस कृत्य के लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से निरहित किया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

शिमला, 21 फरवरी, 2004

संख्या पी० सी० एच० एस० एम० एल० (4)/96-1318-22.—एतद्वारा श्री सुरजन सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत दनगांव, विहास खण्ड रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि० प्र०) का ध्यान हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ग) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जानियत है :—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिये निरहित होगा, "यदि उसने, राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसायटी की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या

अभिहित किन्ती भूमि का अधिग्रहण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे उससे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिकांता न रहा हो"।

यह कि श्री कमल सिंह, ग्राम पंचायत दलगांव, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला से प्राप्त शिकायत पत्र पर तहसीलदार रोहड़ू, के माध्यम से कारवाई गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट से यह पाया गया कि श्री सुरजन सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत दलगांव कि मिसन कब्जा नाजायज नं० 90 वाकत सरकारी भूमि खसरा नं० 690 व 691 रकबा तादादी 0-16-76 है० बाका चक खणकण्डी, तहसील रोहड़ू, दौराने बन्दोबस्त सरतव हुई है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त श्री सुरजन सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत दलगांव द्वारा वर्ष 2000 में उप-प्रधान पद के निर्वचनार्थ नामांकन पत्र दायर करते समय सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा न होने वारे झूठी घोषणा की गई है, जबकि तहसीलदार रोहड़ू के कार्यालय में सिसल कब्जा नाजायज नं० 90 वाकत सरकारी भूमि खसरा नं० 690 व 691 रकबा तादादी 0-16-70 है० बाका चक खणकण्डी, तहसील रोहड़ू, दौराने बन्दोबस्त प्रस्तुत की है। इसलिये (हि० प्र०) पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार वह ग्राम पंचायत दलगांव के उप-प्रधान के पद पर बने रहने के लिये निरहित है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (2) के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उक्त श्री सुरजन सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत दलगांव, विकास खण्ड रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि० प्र०) को कारण बताओ नोटिस जारी करत हूँ कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें इस कृत्य के लिये (हि० प्र०) पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से हटा कर ग्राम पंचायत, दलगांव के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

हस्ताक्षरित/-
एस० के० बी० एस० नेगी,
उपायुक्त, शिमला,
जिला शिमला (हि० प्र०)।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SHIMLA, DISTRICT SHIMLA,
HIMACHAL PRADESH

ORDER

Shimla-1, the 23rd February, 2004

No. SML-PSH(1)/90-38-53.—WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned that some organisations propose to hold rallies, demonstrations, shout slogans, hold public meetings, play band and carry objects capable of being used as weapon of offence, which may disturb public order.

WHEREAS, I, S. K. B. S. Negi, IAS, District Magistrate, Shimla, am satisfied that to maintain public order, it is necessary to prohibit holding of rallies, demonstrations, shouting of slogans, holding of public meetings and carrying of objects capable of being used as weapon of offence;

WHEREAS, I am further satisfied that this order should be passed *ex parte* and with immediate effect keeping in view the urgency and necessity for maintenance of public order.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in me under section 6 of Punjab Security of State Act, 1953 as applicable to Himachal Pradesh, I, S. K. B. S. Negi, IAS, District Magistrate, Shimla, do hereby prohibit the holding of public meetings taking out procession, rallies, demonstrations, shouting of slogans, playing of band and carrying of objects capable of being used as weapon of offence on the Mall road from (i) Chhota Shimla upto Kannedy House and the Ridge (ii) 150 meters on the approach from Rendezvous Restaurant to Rivoli Cinema, (iii) Scandle Point to Kali Bari Temple, (iv) The link Road from Chhota Shimla Gurudwara to Chhota Shimla Kasumpti Road, (v) Chhota Shimla Chowk to Raj Bhawan to Oak Over, (vi) Upto Boundary building on Chhota Shimla Kasumpti Road, (vii) Stairs and pedestrian path adjacent to Chhota Shimla Gurudwara leading to Kasumpti road (viii) Link road from Cart Road to the office of H.P. Administrative Tribunal, (ix) The road leading from A. G. Office to Cart Road, (x) A.G. Office to Vidhan Sabha, (xi) CPWD office to Chaura Maidan for maintenance of public order.

This order shall however, not be applicable to the Police/Para Military/Military Personnel while performing their duties as also on funeral procession and marriage parties.

This order shall come into force at once and shall remain in force upto 28-2-2004.

Given under my hand and seal of the office on this 23rd day of February, 2004.

Sd/-
District Magistrate,
Shimla.

कार्यालय नगर पंचायत नारकण्डा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

शिमला, 13 फरवरी, 2004

पृष्ठांकन संख्या यू० 23.—हिमाचल सरकार की अधिसूचना संख्या यू० डी० एफ० (4)-5/98-III, दिनांक 3-8-2000 के द्वारा हिमाचल प्रदेश गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1979 (1979 का 19) की धारा 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सचिव नगर पंचायत नारकण्डा के क्षेत्राधिकार के अन्दर के निम्न क्षेत्रों को गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित करता हूँ :—

| क्र० सं० | सम्बन्धित क्षेत्र | सीमाएं |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | वार्ड नं० 3 सर्कट हाऊस वार्ड | गणपत मकान से सर्कट हाऊस तक |
| 2. | वार्ड नं० 6 लाल कोठी वार्ड | रैस्ट हाऊस से उच्च विद्यालय, नारकण्डा |
| 3. | वार्ड नं० 7—मेला मैदान वार्ड | जगत राम के घर से रैस्ट हाऊस तक |

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव,

नगर पंचायत नारकण्डा,
जिला शिमला (हि० प्र०) ।

कार्यालय उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

हमीरपुर, 20 फरवरी, 2004

संख्या पंच-हमीर (घलूँ)-690-97.—यह कि श्री रूप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत घलूँ विकास खण्ड नदीन को उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच के आधार पर पत्र सं० पंच-हमीर. (घलूँ), दिनांक 20-10-2003 द्वारा कारण बताओ नोटिस आरोप सूची सहित जारी किया गया था। आरोप सूची में दर्ज आरोपों वाले उक्त प्रधान में प्राप्त उत्तर, जो कि खण्ड विकास अधिकारी, नदीन के माध्यम से प्राप्त हुआ है, की समीक्षा करने पर उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया और प्रधान के विरुद्ध लगाए गए निम्नलिखित आरोप सिद्ध होते हैं:—

1. दिनांक 11-9-2002 तथा 26-9-2002 को पंचायत कोरम अपूर्ण यानि उपस्थिति 3/7 होने पर भी पंचायत कार्यवाही लेखबद्ध करवाकर अवैध प्रस्तावों द्वारा बैंक खातों में राशि निकाली गई तथा 11-9-2002 की कार्यवाही भी बन्द नहीं की गई।
2. श्री रूप सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत (घलूँ) ने 11वें वित्तायोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि को शैल्फ वर्ष 2002-03 में स्वीकृत स्कीमों अनुसार व्यय न करके रा० प्रा० पा० घलूँ में दरवाजे, गलेज जोड़ी-पल्ले लगवाने हेतु अवैध रूप से व मनमर्जी से व्यय किया है।
3. श्री रूप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत घलूँ ने जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की राशि को शैल्फ वर्ष 2002-03 में स्वीकृत स्कीमों अनुसार व्यय न करके अवैध रूप से व मनमर्जी में हेण्ड पम्प, कूआ साई पर व्यय किया गया।
4. प्रस्ताव सं० 5, दिनांक 26-9-2002 (अवैध प्रस्ताव) के तहत श्री रूप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत घलूँ ने बैंक खाता से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मु०/- 11,400 रुपये, दिनांक 28-10-2002 को निकालकर एवं पंचायत से अग्रिम वावन निर्माण प्राप्त करके इस राशि का 28-10-2002 से 6-2-2003 तक तथा इसी राशि में से मु० 8008/- रुपये, दिनांक 7-2-2003 से 23-3-2003 तक नकद तौर पर अनाधिकृत रूप से अपने पास रख कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है।

और क्योंकि श्री रूप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत घलूँ के विरुद्ध उक्त आरोपों पर निष्पक्ष रूप से आगामी कार्यवाही करने के लिए उन्हें उनके पद से निम्नित करना अनिवार्य है।

अतः मैं, देवेश कुमार (भा० प्र० से०), उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(1) तथा हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम (142) (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रूप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत घलूँ, विकास खण्ड नदीन को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करना हूँ तथा उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने पद का कार्यभार उा-प्रधान ग्राम पंचायत घलूँ को तुरन्त सौंप दें और यदि उनके पास कोई ग्राम पंचायत की सम्पत्ति या धन-राशि हो तो उसे भी पंचायत सचिव के पास सौंप दें।

कारण बताओ नोटिस

हमीरपुर, 23 फरवरी, 2004

संख्या पंच-हमीर (जाहूँ)-699-705.—यह कि अध्यक्ष लोकमित्र परियोजना हमीरपुर के माध्यम से समस्त निवासी ग्राम पंचायत जाहूँ का प्रधान, ग्राम पंचायत जाहूँ के विरुद्ध गुजरात भूकम्प राहत को राशि

को गायब करने बारे प्राप्त शिकायत पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी भोरंज से छानबीन कराई गई। उससे प्राप्त जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने पर श्री राम रखा, प्रधान, ग्राम पंचायत जाहू के विरुद्ध गुजरात भूकम्प राहत हेतु एकत्रित राशि बारे इस कारण बताओ नोटिस के साथ संलग्न आरोप सूची में दर्ज आरोप प्रमाणित हुये हैं।

अतः इससे पूर्व कि श्री राम रखा, प्रधान, ग्राम पंचायत के विरुद्ध आगामी कार्यवाही की जाए, मैं, देवेश कुमार (भा० प्र० से०), उपायुक्त हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (1) (क) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राम रखा, प्रधान, ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज को यह कारण बताओ नोटिस जारी करके आदेश देता हूँ कि वह आरोप सूची में दर्ज आरोपों बारे अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी भोरंज के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करे। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 व 146 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अधीन उसके खिलाफ आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी।

देवेश कुमार (भा० प्र० से०),
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

श्री राम रखा, प्रधान, ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज के विरुद्ध जारी आरोप सूची :

आरोप नं०-1 : ग्राम पंचायत जाहू ने प्रस्ताव संख्या 1, दिनांक 4-2-2001 पारित करके गुजरात में आए भूकम्प के पीड़ितों की सहायताय राशि एकत्रित करने हेतु रसीद बुकें छपवाने का निर्णय लिया। प्रस्ताव में दर्ज विवरण अनुसार 10 रसीद बुकें छपवानी थी। परन्तु छपवाई गई रसीद बुकें स्टॉक दर्ज न कराई गई। जोकि एक गम्भीर लापरवाही है जिसके लिए प्रधान व तत्कालीन पंचायत सचिव दोषी हैं।

आरोप नं०-2 : उक्त छपवाई गई रसीद बुकों को पंचायत सदस्यों को लोगों से राशि एकत्रित करने हेतु दिया गया। परन्तु इनका भी कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है जबकि रिकार्ड रखना अनिवार्य था। इन रसीद बुकों में से 8 रसीद बुकों में एकत्रित राशि, जो मु० 3910/- रुपये बनती है, सम्बन्धित सदस्यों ने प्रधान श्री राम रखा के पास लगभग तीन वर्ष पूर्व जमा करा दी थी। परन्तु प्रधान ने इस राशि को न तो सम्बन्धित विभाग को भेजा और न ही इस राशि को पंचायत लेखा में जमा किया। इस तरह प्रधान ने लोगों से प्राप्त राशि को निजी प्रयोग में लाकर इसका दुरुपयोग किया है।

आरोप नं० 3 : श्री धनी राम व सर्वजीत सदस्यों के पास दी गई रसीद बुकों व राशि प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही न करना। जबकि प्रधान होने के नाते यह उनका कर्तव्य था। जिससे स्पष्ट है कि उसका इस राशि को गबन करने का इरादा था।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन-173001, 13 फरवरी, 2004

क्र० सं० पी० सी० एन०-एम० एम० आर० (5) 50 (11)/96-607-14.—यह कि सहायक आयुक्त (विकास), विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर द्वारा सूचित किया गया है कि श्री ईशा पुत्र श्री सफी, जोकि ग्राम पंचायत अजौली के वार्ड नं०-2 —नरैणगढ़ (नारीवाला) का सदस्य था, की मृत्यु दिनांक 2-11-2003 को हो चुकी है।

अतः मैं, एम० एल० शर्मा (भा० प्र० से०), उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड पांवटा साहिब के वार्ड नं०-2 —नरैणगढ़ (नारीवाला) के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूँ।

एम० एल० शर्मा,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन (हि० प्र०)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 10 फरवरी, 2004

क्रमांक पीसीएन-एसएमआर (धारा 122)/2003-526-34.—यह कि श्री सही राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रेडली, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का त्याग-पत्र हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के अन्तर्गत अयोग्यता के दृष्टिगत खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगडाह के माध्यम से दिनांक 30-1-2004 को अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है।

अतः मैं, एम०एस० नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 (3) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (2) के अन्तर्गत कथित श्री सही राम, उप-प्रधान का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूँ।

आदेश द्वारा,

एम० एस० नेगी,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित